DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, hon. Minister has referred to the ongoing process of modernisation of the Central Para-military Forces as part of the process of dealing with the terrorist activities. Sir, through you, I wish to draw the attention of the hon. Minister to the thought-provoking book that has been authored by one of the very distinguished Members of this House, Gen. Shankar Roy Chowdhury, in which, I think, serious doubts have been cast about the ability of the Central Para-military Forces to cope with the challenges that we face in dealing with counter-insurgency. Would the hon. Minister enlighten us as to what is this modernisation that he has in mind when he replied to this question?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, as far as modernisation of police forces and Paramilitary Forces is concerned, we have worked out a scheme under which we are giving grants and loans to the State Governments. We are giving enough money.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I am talking about the Parliamentary Forces.

SHRI HARIN PATHAK: We are providing enough money to the Central Forces, if it is required by them.

DR. MANMOHAN SINGH: You should study that book.

Mineral and metal wealth in reserved forest areas and tribal areas

*384. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether reserved forest areas and tribal areas are bestowed with precious mineral and metal wealth; and

(b) if so, the action to explore the top minerals from those areas ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Survey by Geological Survey of India suggests that forest and tribal areas in India have mineral potential. The National Mineral Policy, 1993, *inter alia* recognizes that the policies governing the mining and

mineral sector should be harmonized with the policies governing industrial and socio-economic developments in the country. The National Mineral Policy, 1993, envisages that extraction and development of minerals are closely interlinked with other natural resources like land, water, air and forest. The areas in which minerals occur often have other resources presenting a choice of utilization of land. Some such areas are ecologically fragile and some are biologically rich. It is necessary to take comprehensive view to facilitate the choice or order of land use keeping in view the needs of development as well as needs of protecting the forests, environment and ecology. Both aspects have to be properly coordinated to facilitate and ensure a sustainable development of mineral resources in harmony with environment.

The Mining statute provides for clearances from the Ministry of Environment and Forests from the environmental and forest angles before exploitation of minerals. Through constant dialogue with the Ministry of Envitronment and Forests, significant procedural simplifications in obtaining forest clearance and environmental clearance for mining activities have come about. This includes the procedure to be follwed for renewal of mining leases and the simplification of the forms. The environment and forestry related issues get discussed in various forums like meetings of the Mineral Advisory Council, Conference of State Ministers of Mining and Geology and Investor meets. The Ministry of Mines constantly interacts with the Ministry of Environment and Forests on the action points arising out of these meetings.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, according to the answer, under the National Mineral Policy, 1993, it is necessary to take comprehensive view to facilitate the choice of the land keeping in view the needs of development as well as needs to protect the forest, environment and ecology. Both aspects have to be properly co-ordinated to facilitate ensured sustainable development of mineral resources in harmony with environment. In this regard, I want to know from the hon. Minister whether any expert committee or foreign consultants have been appointed to advise the Government for better exploration and utilisation of mineral wealth for the all-round development of the country. And, the (b) part of my question is: how many cases have been registered against the people who are doing illegal exploration?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, वैसे विदेशी experts की कोई कमेटी नहीं बनाई गई है लेकिन आज पूरे देश में जो स्थिति बनी है, अर्थव्यवस्था ओपन हो चुकी है, FDI की अनुमति मिल चुकी है। सरकार ने एक reconnaissance permit का concept शुरू किया है जिसमें विदेशी कंपनियां भी भाग ले सकती हैं लेकिन उन्हें अपनी कंपनी को भारतीय कंपनी ऐक्ट के तहत रजिस्टर कराना होता है। अभी तक देशी और विदेशी कंपनियों की सबसीडियरी को मिलाकर कुल 119 reconnaissance permit जारी किए जा चुके हैं जो पूरे देश में विभिन्न खनिजों के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं।

जहां तक अवैध उत्खनन का सवाल है, यह राज्य सरकार का मामला है। अवैध उत्खनन राज्य सरकारों को ही देखना होता है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, how many cases against persons for illegal exploration are pending?

श्री रमेश बैस: कृपया आप सवाल फिर से पूछिए।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I want to ask to how many cases against persons for illegal exploration are pending? How many proposals are pending?

श्री सभापति: इललीगल माइनिंग के कितने केसेज हैं?

श्री रमेश बैस: चूंकि अवैध उत्खनन को रोकने का काम राज्य सरकारों का है इसलिए केन्द्र सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं होता।...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: हो गए आपके दो क्वेश्चन।...(**व्यवधान**)

श्री रमेश बैस: प्रश्न में पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं है लेकिन आपको मैं जानकारी भिजवा दूंगा।

MISS MABEL REBELLO: Sir, in certain tribal areas—just now the Minister said that it is the State Government which has to do it—coal is explored by the Central Government, and the State Governments get some revenue, by way of some cess or royalty. So, when the Government does exploration in tribal areas and take out coal, iron ore, oil, etc., I would like to know from the hon. Minister as to what are the benefits the tribals of these areas get. They do not get the Area Development Fund. They do not get anything. Why is it that the Central Government is not making some special provisions for those areas

where oil or iron ore exploration is carried out and resources are taken out? Do they have any plans in future to make some provision for them?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत अच्छा है।...(व्यवधान)

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, प्रस्ताव अच्छा है परन्तु करेंगे नहीं। ये गरीबों के खिलाफ हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दीजिए, आपकी तारीफ हो रही है।...(व्यवधान)

श्री रमेश बैस: माननीय सदस्या ने कोल के बारे में पूछा है, केवल...(व्यवधान) ट्राइबल क्षेत्रों में जो दोहन का सवाल है, सरकार ऐसे क्षेत्रों में दोहन के लिए वहां के बनवासियों को काम मिले इसका भी ध्यान रखती है। जहां पर आदिवासी क्षेत्रों में अवैध उत्खनन का मामला है, केन्द्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ नियम बनाकर राज्य सरकारों को दिए हैं। एम॰एम॰आर॰डी॰ एक्ट 1957 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन दंडनीय अपराध है। इसमें पहले पांच हजार का जुर्माना होता था जिसको बढ़ाकर 25 हजार किया गया है तथा एक वर्ष की सजा को दो वर्ष किया गया है। अब चूंकि यह राज्य सरकारों को करना है अत: केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्देश देती रही है।

श्री सभापति: आपको तो एलाउ करना ही मुश्किल है। बैठ जाएं।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, it is a fact that there are many precious minerals available all over the country. Is the Government having any proposal to declare the areas as 'safety zones' where previous minerals and mineral wealth are available?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न का जवाब दिया है, सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि सुरक्षित किया जाए, चूंकि Reconnaissance permit के कारण सारे लोगों को सर्वे के लिए अनुमति दी जाती है। एरिया सर्वे होने के बाद पता चलता है कि कहां पर कौन सा मिनरल है उसके बाद उसके दोहन की प्रक्रिया होती है। वन क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में सर्वांगीण विकास होना चाहिए इसके लिए सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध बहुमूल्य खनिजों के उत्खनन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में यथासंभव अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है। खनिजों के दोहन और संरक्षण में परस्पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों के मंत्रियों की बैठक लेती रहती है और इनको निर्देश देती रहती है।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न अभी कुमारी मैबल रिबैलो ने किया था। प्रश्न यह है कि जिन आदिवासी क्षेत्र में उत्खनन होता है, तो वहां के आदिवासियों को उस पूरे ऑपरेशन में या पूरी एक्सरसाइज में कोई लाभ देने का भी कार्यक्रम आपके अंदर है या नहीं है या केवल वे खड़े होकर देखते रहे और मजदूरी लेकर घर चले जाएं तथा आप करोड़ों की सम्पत्ति उनकी जमीन से निकाल कर ले जाएं। तो क्या उनका भी कोई हिस्सा है या नहीं है?

श्री रमेश बैस: सभापति महोदय, विभिन्न खनन क्षेत्रों में जो भी खनन का कार्य होता है या जो भी काम लेते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उन्हें काम देना चाहिए। वहां पर उनके लिए रहने की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है। स्थाई क्षेत्र का विकास करते हुए, वहां पर विकास के लिए अस्पताल है, विद्यालय है, पीने का पानी है, सड़क है। इनका विकास करने के लिए भी उनकी जवाबदारी होती है, जो भी उनसे काम लेते हैं, यह उनकी जवाबदारी होती है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन

*385. **श्री अभय कांत प्रसाद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा आज तक स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन हेतु कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या हाल में अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन समाप्त कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गोवा मुक्ति संग्राम के स्वतन्त्रता सेनानियों को आज तक कोई राशि अथवा पेंशन नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विगत वर्षों के दौरान तथा 28.2.2003 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पर किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है: